

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य महाप्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड जल संस्थान,  
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 24 जून, 2011

**विषय :-** जनपद देहरादून नगर की विजय कालोनी, डोभालवाला जोन में मिनी नलकूप के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1031 / अप्रै0-03 / प्राक्कलन (मु0) / 2011-12 दिनांक 11.05.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में जनपद देहरादून नगर की विजय कालोनी, डोभालवाला जोन में मिनी नलकूप के निर्माण हेतु गठित प्राक्कलन ₹ 26.91 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 26.88 लाख (₹ छबीस लाख अद्वासी हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

4- कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

5- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापित न किया जाय। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों को अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

7- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9- कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेता से कार्य स्थल का भली भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

10- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैरिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

11- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

12- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कढाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-03-नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन/जीर्णद्वारा/सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 221/XXVII (2)/2011 दिनांक 21 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

अपर सचिव

पृष्ठ 622 (i) / उन्तीस(2)/ 11-2(22पे0) / 2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल) / राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

२०१८  
(गरिमा सैकली)

उप सचिव